शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक-1 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 30-06 जनवरी 2025 मूल्य पांच रूपये

टैंकर सप्लाई घोटाले से सुक्खू सरकार आयी सवालों में

- क्या इस तरह का घोटाला प्रदेश के अन्य भागों में भी घटा होगा उठने लगा सवाल
- क्या राजनीतिक संरक्षण के बिना ऐसा हो सकता है?
- क्या शिमला जिले के नेताओं का सूचना तन्त्र सही में कमजोर है?

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार ने विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र में पुलिस अधिनियम में संशोधन करके प्रदेश में किसी भी सरकारी कर्मचारियों को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस संशोधन के बाद पुलिस किसी भी आपराधिक मामले में सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह संशोधन केन्द्र से अनुमोदन मिलने के बाद कानून बन जायेगा। इस संशोधन से सरकार की नीयत और नीति का पता चल जाता है। वैसे इसी सत्र में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून लाने की भी घोषणा की है। सरकार जब सदन में यह सब कर रही थी तब शिमला के ठियोग में पानी सप्लाई का बहुचर्चित घोटाला घट चुका था। इस घोटाले की जानकारी सरकार को भी हो चुकी थी। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के मुताबिक टैंकर वाले ने ही नवम्बर में एक पत्रकार वार्ता करके इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। जयराम के मुताबिक इस घोटाले की शिकायत काफी समय तक एसडीएम ठियोग के पास लंबित रही है। एसडीएम के पास ऐसी शिकायत आने का अर्थ है कि प्रशासन के उच्च स्तरों तक भी इस घोटाले की सूचना रही होगी। घोटाले में जिस तरह से दस छोटे-बड़े अभियंताओं को निलंबित किया गया है और जितनी पेमेंट्स इसमें हो चुकी है उससे इस घोटाले का आकार सामने आ जाता है। इसमें जितने लोगों को निलंबित किया गया है उसमें एक मृतक व्यक्ति भी एक भाजपा पदाधिकारी के ब्यान के मुताबिक शामिल है। इससे यह सामने आता है कि इस घोटाले की जांच कितनी गंभीरता से की जा रही है। इसी के साथ यह सवाल उठना भी स्वभाविक है कि यदि ठियोग में यह सब घट सकता है तो प्रदेश के अन्य भागों में क्यों नहीं जहां भी इस तरह से पानी की सप्लाई की गई होगी।

ठियोग क्षेत्र शिमला राजधानी से सटा है। शिमला जिले से मंत्रिमंडल में तीन मंत्री हैं। शिमला से ताल्लुक रखने वाले सलाहकार और ओ.एस.डी. भी मुख्यमंत्री की टीम में शामिल हैं। शिमला में इतना राजनीतिक प्रतिनिधित्व सरकार में होते हुये भी इस घोटाले की भनक तक न लग पाना अपने में ही कई सवाल खड़े कर जाता है। क्या इन राजनेताओं का सूचना तंत्र इतना कमजोर था? जबकि सरकार में लोक निर्माण और जल शक्ति विभागों में सप्लायर बनने के लिये राजनीतिक रिश्ते होना एक अघोषित और व्यवहारिक शर्त रहती ही है। फिर यह सवाल आता है कि जब टैंकरों से पानी सप्लाई करने की आवश्यकता महसूस की गई होगी तब सबसे पहले उन गांव की सूची तैयार की गई होगी जहां पानी सप्लाई किया जाना था। यह रिकॉर्ड पर आया होगा कि वहां सड़क है या नहीं। घोटाले के विवरण में यह सामने आया है कि जहां सड़क ही नहीं थी वहां भी गाड़ियों से सप्लाई दी गई और कई चक्कर लगाये गये। इससे यह सवाल उठता है कि कहीं उन गांवों को भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क से जुड़ा हुआ तो नहीं दिखा रखा है। अन्यथा कोई भी अधिकारी रिकॉर्ड पर इतनी गलती करने की मूर्खता नहीं करेगा की सड़क न होते हुये भी गाड़ी से वहां पानी की सप्लाई का ऑर्डर दे दें। इससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी जांच के दायरे में आ जाती है। यदि अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस सब को नजरअंदाज करते हुये इस तरह के कारनामों को अंजाम दे दिया है तो इससे स्पष्ट हो जाता है की पूरी व्यवस्था ही नीचे तक भ्रष्ट हो चुकी है।

इसी के साथ क्षेत्र के स्थानीय नेतृत्व जिसमें पंचायत बी.डी.सी. और जिला परिषद तक सब सवालों के घेरे में आ जाते हैं। जिस तरह का घोटाला घटा हुआ लग रहा है उसमें ऐसा लगता है कि सब कुछ एक दफ्तर में बैठकर ही अंजाम दे दिया गया। जहां करोड़ों में पेमैन्ट हुई है उसमें अच्छे स्तर का

शेष पृष्ठ 8 पर.....

रेरा में अध्यक्ष और सदस्यों के पद भरने के लिये जारी हुआ विज्ञापन

- विज्ञापन में विजिलैन्स क्लीयरैन्स पर मौन
- केन्द्र द्वारा 9-10-24 को जारी निर्देशों से उठी चर्चा

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने रेरा में अध्यक्ष और सदस्यों के पद भरने के लिये प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिये पात्र सदस्यों से 23 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गये हैं। पूर्व में सेवानिवृत आई.ए.एस. अधिकारी ही इन पदों के लिये चयनित होते रहे हैं और इस बार भी इसमें कोई अपवाद होने की संभावना कम ही है। लेकिन सेवा अधिकारियों के विजिलैन्स क्लीयरैन्स के लिये जो दिशा-निर्देश जारी किये हैं उनके परिदृश्य में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को विजिलैन्स क्लीयरैन्स हासिल करना कठिन हो सकता है। इन निर्देशों के मुताबिक विजिलैन्स मामले झेल रहे अधिकारियों के लिये इन पदों के चयन के दायरे में आ पाना कठिन होगा। बल्कि इन निर्देशों के अनुसार ऐसे मामले झेल रहे अधिकारी तो संवेदनशील पदों पर भी नियुक्त नहीं किये जा सकते। ऐसे अधिकारियों को पुनः नियुक्ति देना संभव ही नहीं है। फिर रेरा के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन में प्रदेश उच्च न्यायालय का भी दखल है।

यह है भारत सरकार के दिशा- निर्देश

AVD(AVD-IA)

North Block, New Delhi
Dated 09 October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Revised Guidelines regarding grant of 'Vigilance Clearance' to AIS Officers & Central Civil Services/Central Civil posts

No. 104/33/2024-AVD-IA
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated the 9th October 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Revised Guidelines regarding grant of 'Vigilance Clearance' to AIS Officers & Central Civil Services/Central Civil posts.

D/o Personnel & Training (DoPT) has from time to time issued instructions / guidelines regarding grant of Vigilance Clearance to AIS officers &Central Civil Services/Central Civil posts. An effort has been made to revise the said guidelines for better understanding and guidance.

Part A-Grant of Vigilance Clearance to AIS Officers

2. These orders shall be applicable to vigilance clearance with respect to:

(i) Inclusion in the offer list
(ii) Empanelment
(iii) Ex-India study leave
(iv) Cases of inter-cadre transfer and extension thereof
(v) Any deputation, including inter-cadre deputation and extension thereof
(vi) Appointments to sensitive posts
(vii) Assignments to training programmes except mandatory training

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने मनाया स्थापना दिवस

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के स्थापना दिवस समारोह और हिमाचल आपदा तैयारी माह के समापन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम

करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। राज्यपाल ने उत्कृष्ट प्रयासों, सामाजिक जुड़ाव और योगदान के लिए एचपी-एसडीआरएफ की सराहना की।

राज्यपाल ने एचपी-एसडीआरएफ को स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर आपदाओं के आर्थिक और मानवीय मूल्य को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि भारत में आपदाओं के कारण अनुमानित वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्यों को आर्थिक नुकसान कम करने और बहुमूल्य जीवन को बचाने में मदद की है।

राज्यपाल ने कहा कि भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश को भूस्खलन, भारी बर्फबारी और भूकंप जैसी आपदाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील बनाती हैं। वर्ष 2023 में भीषण बाढ़ और भूस्खलन का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने एक सुदृढ़ आपदा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने एसडीआरएफ की 6 जनवरी, 2020 को स्थापना के बाद से नागरिकों की सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

राज्यपाल ने 148 तलाशी एवं बचाव मिशन आयोजित करने, 302 लोगों की जिंदगी बचाने, 150 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकालने और 117 पीड़ितों के शवों को बरामद करने के लिए एसडीआरएफ की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि चूड़धार में फंसे दो अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित बचाना, श्रीखंड महादेव, मणिमहेश तीर्थयात्राओं और मंडी जिले के नगवाई में रेस्क्यू एसडीआरएफ के उल्लेखनीय अभियान रहे।

उन्होंने आपदा प्रतिक्रिया कार्यों में ड्रोन जैसे उन्नत उपकरणों को एकीकृत करने, गोताखोरी, पर्वतारोहण और चिकित्सा प्राथमिक प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों को दिए गए विशेष प्रशिक्षण के लिए एसडीआरएफ की सराहना की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने नौ स्वयंसेवकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। इनमें संत निरंकारी चेरिटेबल फाउंडेशन (एसएनसीएफ), शिमला जोनल इंचार्ज कप्तान एनपीएस भुल्लर, बाबासाहेब अंबेडकर वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह मट्टु, एडुकेयर धर्मशाला के कार्यक्रम निदेशक हरजीत भुल्लर, डुअर्स एनजीओ के कार्यक्रम निदेशक नवनीत यादव, माहूनाग डाइविंग एसोसिएशन सुन्दरनगर, एआईएमएसएस चमियाना एमबीबीएस रेजिडेंट डॉ. उदय भूषण शर्मा, जिला मंडी के राजवन गांव के राकेश कुमार, विजय कुमार और हिमालयन एडवेंचर सर्च एंड रेस्क्यू टीम भुंतर जिला कुल्लू के छापे राम नेगी शामिल हैं।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवन्त अटवाल त्रिवेदी ने हिमाचल प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया बल की गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह बल साहस और आशा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया माह के दौरान व्यापक आधारभूत सर्वेक्षण, सामुदायिक पहुंच और स्वयंसेवक पंजीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान शिमला, मंडी और धर्मशाला में 2,500 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया और आपदाओं के दौरान सहायता के लिए 650 स्वयंसेवकों को भी पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक अर्जित सिंह ने हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के कार्यों के बारे में अवगत करवाया जबकि डिप्टी-कमांडेंट जनरल गृह रक्षक नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं अरविन्द पराशर ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

राज्यपाल ने नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं दीं हैं।

अपने शुभकामना संदेश में राज्यपाल ने कहा कि नव वर्ष प्रदेशवासियों के जीवन में उत्साह और उमंग लेकर आएगा तथा प्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के लोगों के समर्पण भाव और कड़ी मेहनत के बल पर हिमाचल प्रदेश वर्ष 2025 में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

राज्यपाल ने तांदी गांव के लिए राहत सामग्री वाहन रवाना किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन, शिमला से

राज्य रेडक्रॉस के माध्यम से कुल्लू जिला के बंजार उप-मंडल स्थित तांदी गांव में लगी भीषण आग से प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री का वाहन रवाना किया। उन्होंने पांच जिलों के लिए शीतकालीन राहत सामग्री के पांच अन्य वाहनों को भी रवाना किया। राज्यपाल ने तांदी गांव में आग लगने की घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना में स्थल की धरोहर को व्यापक क्षति हुई है। इस घटना में हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि तांदी गांव में राहत कार्यों के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रेडक्रॉस ने राहत सामग्री के रूप में प्रभावितों के लिए कम्बल, तिरपाल, रसोई सेट, फैमिली टैंट इत्यादि भेजे हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राहत सामग्री भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला किन्नौर, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना में शरद ऋतु के दृष्टिगत जरूरमंद लोगों के लिए राहत सामग्री के पांच अन्य वाहन भी रवाना किए गए हैं।

आईजीएमसी, टांडा और नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में थ्री टेस्ला एमआरआई मशीनों के लिए 85 करोड़ रुपये आबंटित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने थ्री टेस्ला एमआरआई मशीनों की खरीद के लिए 85 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिन्हें आईजीएमसी शिमला, टांडा चिकित्सा महाविद्यालय और नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि थ्री टेस्ला एमआरआई मशीन एक अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण है। इन मशीनों के स्थापित होने से सटीक और गहन विश्लेषण की आवश्यकता वाले चिकित्सा मामलों में सहायता मिलेगी तथा बीमारियों का उपचार किया जा सकेगा, जिससे मरीजों को बेहतर ईलाज की सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए आगामी समय में प्रदेश सरकार 1500 करोड़ रुपये के निवेश से स्वास्थ्य संस्थानों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करेगी। वर्तमान में राज्य के 9.5 लाख लोग बेहतर उपचार सुविधा के लिए प्रदेश से बाहर का रूख करते हैं, जिससे सकल घरेलु उत्पाद की 1350 करोड़ रुपये की क्षति हो रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उन्नत चिकित्सा उपकरण स्थापित करने की दिशा में प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सेमी ऑटोमेटिक लेबोरेटरीज, अल्ट्रासाउंड मशीनों और आईसीयू सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसके साथ सभी सिविल और जोनल अस्पतालों में पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऐनेलाईजर, डिजिटल एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड मशीनें और मॉडयूलर ऑपरेशन थियेटर शीघ्र ही स्थापित किए जाएंगे। इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है, इनहाउस लैब की सुविधा से मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा और डॉक्टर उनके रोग का निदान कर सकेंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं को हाशियें पर रखने के लिए पिछली भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली पर बुरा असर पड़ा और सरकारी स्वास्थ्य संस्थान रेफरल अस्पताल बन गए। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण लोगों की मेहनत की कमाई और बहुमूल्य समय की बर्बादी हुई। इसके विपरीत कांग्रेस सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है और लोगों को शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

लोक निर्माण मंत्री ने तांदी गांव में प्रभावितों से भेंट की

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू के बंजार

विधानसभा क्षेत्र के तांदी गांव में लगी भीषण आग से प्रभावित लोगों से भेंट की और उनका कुशल-क्षेम जाना। इस भीषण दुर्घटना में 17 घर और गौशालाएं जलकर राख हो गई।

प्रभावित परिवारों से बातचीत करते हुए लोक निर्माण मंत्री ने उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गांव के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

विक्रमादित्य सिंह ने सभी प्रभावित परिवारों को राशन किट वितरित किए और कहा कि उन्हें संशोधित राहत नियमावली के अंतर्गत शीघ्र ही राहत राशि प्रदान की जाएगी।

हरित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् हरित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत शिमला में जनवरी माह में दो प्रमाण-पत्र पाठयक्रम आयोजित करेगी। इन पाठयक्रमों को वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। यह पाठयक्रम मधुमक्खी पालन और प्रकृति संरक्षक व ईको पर्यटन गाइड विषयों पर आधारित होंगे।

हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् के सदस्य सचिव डीसी राणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि परिषद् द्वारा राज्य में स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन पाठयक्रमों के तहत युवाओं को मधुमक्खी-पालन तकनीक, उनके पर्यावरणीय और व्यावसायिक लाभ और सतत् पर्यटन के विभिन्न आयामों की जानकारी प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। युवाओं को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निःशुल्क आवास और भोजन इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण पर इस तरह के प्रशिक्षण पाठयक्रमों के अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में हिमकोस्ट द्वारा राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के माध्यम से पर्यावरण पर लोकप्रिय व्याख्यान श्रृंखला भी आयोजित की जा रही है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मंत्रीमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित

शिमला/शैल। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों को हस्तांतरित की गई भूमि की समीक्षा की गई। बैठक में अवगत करवाया गया कि राजस्व विभाग द्वारा 30 नवंबर, 2024 तक विभिन्न विभागों को 31,031 बीघा भूमि हस्तांतरित की गई है। उद्योग विभाग को 20,562 बीघा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत को 2,309 बीघा, पशुपालन विभाग को 2,942 बीघा और पर्यटन एवं नागरिक उड्ढयन विभाग को 628 बीघा भूमि हस्तांतरित की गई है।

राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को सभी विभागों और जिलों से हस्तांतरित की गई भूमि में से प्रयोग न की गई भूमि का ब्यौरा मांगने के निर्देश दिए। इस संबंध में सभी जिलों और विभागों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। मंत्रिमंडलीय उप-समिति की आगामी बैठक में प्रयोग नहीं की गई भूमि के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा, निदेशक कृषि कुमुद सिंह, निदेशक उद्योग युनूस, अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान चंद, पशुपालन और पर्यटन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने हिप्पा का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नाम पर करने की घोषणा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा), शिमला की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्व. डॉ. मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की। उन्होंने हिप्पा में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और कहा कि उनकी दुरदर्शी नीतियों के कारण देश के लोग आत्म-सम्मान के साथ खड़े हैं और हिमाचल प्रदेश के विकास में भी उनका विशेष योगदान रहा है। उनके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में अनेक बड़े संस्थान खुले, जिसका लाभ आज प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिप्पा की एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया।

उन्होंने हिप्पा में स्पेशल एजुकेटर की तीन जनवरी तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया, जिसमें 80 शिक्षक भाग ले रहे है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को न्यू एज टेक्नोलोजी से विशेष बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे दृष्टिबाधित बच्चों को लाभ मिलेगा। यह नई पद्धति ब्रेल का स्थान लेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसाधनों में दृष्टिबाधित बच्चों को भी उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के सभी दृष्टिबाधित बच्चों को मिलने वाली 1500 रुपए मासिक पेंशन को 27 वर्ष की आयु तक बढ़ाकर 4 हजार रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसका प्रावधान राज्य सरकार आगामी बजट में करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दृष्टिबाधितों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी संसाधनों से हिमाचल प्रदेश की कुल आय 16 हजार करोड़ रूपये वार्षिक है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर ही सालाना 27 हजार करोड़ रुपये

व्यय होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले समय के लिए हिमाचल प्रदेश की दिशा तय करनी होगी, इसीलिए हम हिमाचल प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि प्रदेश के लोगों का भविष्य सुखमय हो। उन्होंने कहा कि इसमें सभी वर्गो के सहयोग की आवश्यकता है। पिछले दो वर्षो से हमारी सरकार कड़ी मेहनत कर अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में सफल रही है, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने हिप्पा की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर संस्थान के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुशासन कांग्रेस सरकार का मूल मंत्र है और इसके लिए अधिकारियों को बेहतर और तकनीक आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में हिप्पा की विशेष भूमिका है।

सचिव प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण सी. पालरासु ने हिप्पा की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, एपीएमसी शिमला किन्नौर के अध्यक्ष देवानंद वर्मा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, निदेशक हिप्पा रूपाली ठाकुर, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजेश शर्मा और गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने नव वर्ष 2025 की बधाई एवं शुभकामनाएं दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नव वर्ष 2025 के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की कि नव वर्ष सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा और हिमाचल प्रदेश विकास की नई बुलंदियां हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि देवी-देवताओं और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमने वर्ष, 2024 की हर बाधा को पार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों के सहयोग से वर्तमान सरकार ने हर मुश्किल का सफलतापूर्वक सामना किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है जिसमें प्रदेशवासियों के भरपूर सहयोग की अपेक्षा है।

मुख्यमंत्री ने पॉलिटिव देखभाल वाहन को रवाना किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कैंसर रोगियों व अस्पताल जाने में असमर्थ और अन्य रोगी जो लंबे समय से बीमार है, को घर-द्वार पर उपशामक देखभाल प्रदान

करने के उद्देश्य से चिकित्सा पेशावरों की एक समर्पित टीम और वाहन को रवाना किया। इस टीम में उपशामक देखभाल में प्रशिक्षित एक चिकित्सक, एक समाजशास्त्री तथा एक नर्स शामिल हैं जो आईजीएमसी शिमला में रेडियोथेरेपी एवं आन्कोलॉजी विभाग के अन्तर्गत रोगियों को स्वास्थ्य देखभाल करेंगे। यह पहल प्रदेश में सिप्ला फाउंडेशन तथा कैनसपोर्ट इंडिया के सहयोग से शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल रोगियों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह टीम रोगियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईजीएमसी शिमला के चिकित्सकों के साथ गहन परामर्श में कार्य करेगी। चिकित्सा देखभाल के अलावा टीम में शामिल समाजशास्त्री रोगियों की सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करेगी और उनकी चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करेंगे।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस पहल के अन्तर्गत मरीजों को दवाइयां और ड्रैसिंग किट निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। शुरूआत में यह सेवा आईजीएमसी शिमला के 40 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले मरीजों को प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहल गंभीर रूप से बीमार मरीजों को विशेष देखभाल प्रदान करने और घर-द्वार पर आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में कारगर साबित होगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

एचपीटीडीसी कार्यालय धर्मशाला स्थानांतरित करने पर विचार कर रही सरकारः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने

की संभावनाएं तलाश रही है। एचपीटीडीसी के कामकाज की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कांगड़ा जिले को राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित गया है और यह कदम जिले में पर्यटन क्षमता का दोहन करने में बेहद मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पहल और निगम के कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों से निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उच्चतम 105 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया है।

उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास निगम की 11 प्रमुख संपत्तियों के जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है तथा यह कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों के कमरों की बुकिंग के लिए मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप आदि अग्रणी ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के रेस्तरां की पहुंच बढ़ाने के लिए स्विगी और जोमैटो के साथ समन्वय करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को पायलट आधार पर पांच संपत्तियों में पंचकर्म स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू करने के लिए आयुष विभाग के साथ समन्वय करना चाहिए ताकि पर्यटकों को प्रदेश में बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने पर्यटकों को आकर्षित करने वाले तथा अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में फूड ट्रक चलाने की संभावनाएं तलाशने तथा मनाली में फ्लाइंग डाइनिंग और ग्लास रेस्तरां स्थापित करने पर विचार करने को कहा। उन्होंने आगंतुकों के लिए विविध व्यंजन परोसने के भी निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, विधायक सुदर्शन बबलू, प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक राजीव कुमार और निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

हयूमन मेटान्यूमोवायरस पर स्वास्थ्य सचिव ने जारी किए दिशा-निर्देश

शिमला/शैल। हाल ही में कर्नाटक राज्य में हयूमन मेटान्यूमोवायरस के रिपोर्ट किए गए मामलों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों व केन्द्रशासित राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि हयूमन मेटान्यूमोवायरस एक सामान्य वायरस है जो यह ज्यादातर बच्चों, वयस्कों और कमजोर प्रतिरक्षा क्षमता वाले लोगों में फैलता है।

भारत सरकार ने कहा है कि यह एक सामान्य वायरस है जिससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वायरस से इन्फेक्शन भारत में पहले भी होते रहे हैं। इसके मुख्य लक्षण खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गंभीर मामलों में सांस का फूलना इत्यादि है तथा इससे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने, छींकने व हाथ मिलाने आदि से फैलता हैं। यह वायरस कोई भी गंभीर बीमारी नहीं करता है। उपरोक्त लक्षण होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर अपनी जांच करवाने की सलाह दी गई है।

भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक के उपरान्त हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यो, सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और सभी चिकित्सा अधीक्षकों के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि इन्फ्लूएंजा से संबंधित मामलों या गंभीर तीव्र श्वसन के सभी मामलों की निगरानी की जाए।

भ्रष्टाचार व विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं:राठौर

शिमला/शैल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार व विकास कार्यो की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में चल रहें सभी विकास कार्यो की गुणवत्ता को वह स्वयं समय समय पर अधिकारियों के साथ परख रहें है।

मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कुलदीप राठौर ने कहा कि ठियोग में पेयजल आपूर्ति में घपले का मामला पहले ही उनके ध्यानार्थ आया है और उन्होंने इस बारे ठियोग के एसडीएम, आईपीएच एक्सईएन सहित जिला के उपायुक्त को इस पूरे मामले की जांच करने को कहा था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर हो सहन नही किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वह भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर कायम है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी जांच जल्द पूरा कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कारवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टि मे इस पूरे मामले में दाल में काला नज़र आता है और जांच रिपोर्ट के बाद ही पूरे तथ्य सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी स्तर पर छोड़ा नही जाएगा।

कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि यहां बने निम्न स्तर के नव निर्मित होस्टल निर्माण को लेकर भी विधानसभा की लोक लेखा समिति ने हिमुडा के निदेशक को अपना पक्ष रखने को बुलाया है। उन्होंने कहा कि इस होस्टल भवन को असुरक्षित घोषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि यहां बने नागरिक अस्पताल का निर्माण भी संतोषजनक नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यो की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।इसकी भी जांच की जा रही है और इसके निर्माण करने वाले ठेकेदार व अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी।

सत्य किसी भी सामूहिक विनाश के हथियार से कहीं अधिक शक्तिशाली है।

..... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

क्या मुफ्ती की घोषणाओं पर विराम लगना चाहियें।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिये जिस तरह का राजनीतिक वातावरण निर्मित होता जा रहा है उसने हर आदमी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। क्योंकि जैसे ही अरविन्द केजरीवाल ने ग्रंथी-पुजारी सम्मान योजना की घोषणा की और उस पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं भाजपा की ओर से आयी हैं उससे चुनाव का पूरा अख्यान ही बदल गया है। दिल्ली में 2014 से आप का शासन है। पिछले दो विधानसभा चुनावो में भाजपा और कांग्रेस की जो परफॉरमैन्स दिल्ली में रही है और इस एक दशक में परोक्ष/ अपरोक्ष जो टकराव भाजपा आप में रहा है उससे एक अलग ही राजनीतिक परिदृश्य उभरा है। इस दौरान जिस तरह के आरोपों से आप नेतृत्व घिरा और जेल तक जाने की नौबत आयी तथा किसी भी आरोप पर अन्तिम फैसला अदालत से नहीं आया है उससे स्थितियां बहुत बदल गयी हैं क्योंकि दिल्ली में देश के शीर्ष संस्थान स्थित है जिनके कारण यहां पर अभी भी बौद्धिकता का वातावरण बहुत हद तक सुरक्षित है। इसी वातावरण का परिणाम है कि जैसे ही ग्रंथी-पुजारी सम्मान योजना की घोषणा हुई उसी के साथ यह तथ्य और आंकड़े सामने आ गये कि देश के किन-किन राज्यों में ऐसी योजनाएं व्यवहार में है। दिल्ली में आप सरकार मस्जिदों के इमामों को वेतन देती आयी है और भाजपा इस पर आप पर मुस्लिम परस्ती का आरोप लगाते रही है। लेकिन अब एक ही झटके में यह आंकड़े और तथ्य सामने आ गये कि कितने भाजपा शासित राज्यों में इमामों को वेतन और वक्फ बोर्डो को आर्थिक अनुदान मिल रहा है।

दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में इमामों को 16000/-रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश में 3000/-से 1560 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में जो मस्जिदें पुरातत्व विभाग की सूची में आ गयी है उनको सरकारें पैसा दे रही है। बिहार में सौ करोड़ प्रतिवर्ष सरकार वक्फ बोर्ड को अनुदान दे रही है जिससे इमामों को वेतन दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में 2012 से ही 2500 रुपये मासिक दिये जा रहे हैं। तेलंगाना में 2022 से इमामों और मुअज्जिनों को 5000/-मासिक दिये जा रहे है।

काशी विश्वनाथ मन्दिर ट्रस्ट ने 2024 से मुख्य पुजारी को 90000/-कनिष्ठ को 80000/-तथा सहायक को 65000/-देना शुरू कर दिया है। अयोध्या राम मन्दिर ट्रस्ट ने मुख्य पुजारी को 38500/-प्रति माह देने का फैसला किया है। आन्ध्र प्रदेश में प्रत्येक मन्दिर को दस लाख और पुजारीयों को 15000/-तथा नाई को 25000/- दिये जा रहे है। वेद पाठ करने वाले युवाओं को प्रतिमाह 2000/- का मानदेय दिया जा रहा है। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि लगभग सभी सरकारें मन्दिरों के पुजारीयों और मस्जिदों के इमामों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। भाजपा शासित राज्यों में भी यह सब हो रहा है। भाजपा विधान सभाओं और संसद के लिये भले ही मुसलमानों को टिकट न दे लेकिन मुस्लिमों के वोटों के लिये इमामों और मस्जिदों को आर्थिक सहायता अवश्य दे रहे हैं।

इस विवरण और केजरीवाल के फैसले के मद्देनजर यह सवाल उठता है कि क्या इस तरह की योजनाओं और ऐसी ही अन्य योजनाओं को मुफ्ती के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए? इस समय देश के चौदह राज्यों में महिलाओं के लिये कैश ट्रांसफर योजना चालू है और इन पर प्रतिवर्ष दो लाख करोड़ खर्च किये जा रहे हैं। कई राज्य मुफ्त बिजली देने की योजनाएं चला रहे हैं और इससे बिजली वितरण कंपनियों को आरबीआई के मुताबिक 6.5 लाख करोड़ का घाटा हो चुका है। रिजर्व बैंक की 2024 की रिपोर्ट में यह सारे आंकड़े हैं। इस समय राज्यों की कुल बकाया देनदारियां जीडीपी के 28.51 प्रतिशत पर खड़ी है। मुफ्ती की योजनाओं से राज्यों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। कर्ज के बढ़ने से ब्याज बढ़ता जा रहा है। ब्याज के बढ़ने से विकास कार्यो के लिये धन की उपलब्धता प्रभावित होती है। मुफ्ती की योजनाएं बन्द होनी चाहिये इस पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आरबीआई तक सभी चिन्ता व्यक्त कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 2013 से इस आशय की याचिकाएं लंबित चली आ रही है। सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग को इस पर राजनीतिक दलों से सुझाव लेकर चुनाव घोषणा पत्रों के लिये एक नीति बनाने का सुझाव दे चुके हैं। प्रधानमंत्री ने जुलाई 2022 में इस पर ब्यान देकर चिन्ता जताई थी लेकिन संसद में ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आ पाये हैं। ऐसे में केजरीवाल की ग्रंथी-पुजारी सम्मान योजना पर उभरी प्रतिक्रियाओं के परिदृश्य में मुफ्ती की घोषणाओं पर एक सार्वजनिक बहस की आवश्यकता है।

स्यांज की महिलाएं खद्दी पर बुन रहीं सुनहरे भविष्य के सपने

मंडी जिला के थमलाह गांव की हीरामणि एक सामान्य गृहिणी हैं। अपने दैनिक कार्य निपटाने के उपरांत खाली समय में वह खद्दी पर कुशलता से अपने हाथ चलाती हैं। अपने इस शौक को हुनर में बदलते हुए उन्होंने हथकरघा क्षेत्र में कई महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। इसमें सहायक बनी हैं हथकरघा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए

संचालित की जा रही प्रदेश सरकार की योजनाएं। इससे स्यांज क्षेत्र की युवतियां सुनहरे भविष्य के सपने साकार करने के साथ ही अपने हुनर से सफलता की नई कहानी लिख रही हैं।

हीरामणि ने बताया कि लगभग अढाई दशक से वह घर में खद्दी का काम करती थीं, परंतु वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के मंडी स्थित अधिकारियों से मिलने के बाद इस कार्य को व्यावसायिक तौर पर आगे बढ़ाने की सोच बनी। इसके लिए स्यांज बाजार में दुकान किराए पर लेकर कार्य आरंभ किया। निगम द्वारा उन्हें मास्टर ट्रेनर के तौर पर कार्य दिया गया। गांव की 8 महिलाओं को हैंडलूम की एक साल ट्रेनिंग दी। ट्रेनर के तौर पर प्रतिमाह 7500 रुपए भी प्राप्त हुए। प्रशिक्षु महिलाओं को भी निगम द्वारा प्रशिक्षण के दौरान एक खद्दी और 2400 रुपए प्रतिमाह की राशि प्रदान की गई।

हीरामणि ने बताया कि आज वह खद्दी व्यवसाय के तहत किन्नौरी व कुल्लू शैली की शॉल व मफलर तैयार करती हैं। इससे वह पंद्रह से बीस हजार रुपये हर महीने कमा रही हैं और परिवार की आर्थिकी में सहयोग कर रही हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी सभी महिलाएं भी अपने-अपने तौर पर कुछ घर से और कुछ उनके साथ दुकान से खद्दी का कार्य कर रही हैं।

उन्होंने प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया कि महिलाओं के सशक्तिकरण व हथकरघा के माध्यम से घर-द्वार पर रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी योजनाएं सराहनीय हैं। इससे महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं।

गांव स्यांज से संबंध रखने वाली भूपेंद्र कुमारी भी उन्हीं की तरह शॉल इत्यादि बुनने का कार्य करती हैं। गरीब परिवार से संबंध रखती हैं और पिता किसान हैं। वर्ष 2023 में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर में ही रही। इस दौरान हीरामणि के प्रोत्साहन से खद्दी का काम करने लगीं। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम द्वारा गांव की महिलाओं को खद्दी का काम सीखने पर अगस्त, 2023 से एक साल की ट्रेनिंग दी गई। इस काम में रुचि होने से प्रशिक्षण आसानी से पूरा हो गया। इस दौरान निगम द्वारा खद्दी प्रदान की गई। ट्रेनिंग के दौरान हर महीने प्रोत्साहन राशि भी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान ही शॉल, मफलर तैयार किए, जिससे अतिरिक्त पैसे मिलना शुरू हो गए। आज वह अपने घर से ही शाल व मफलर का काम कर रही हैं तथा प्रतिमाह दस हजार रुपए तक कमा रही हैं। स्वयं के खर्चे और परिवार की जरूरतें पूरी करने में सहयोग कर रही हैं। ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं चलाने के लिए उन्होंने प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया।

गांव स्यांज से ही संबंध रखने वाली नीलम का कहना है कि वर्ष 2021 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कोरोना काल में वह आगे पढ़ाई जारी न रख सकीं। हथकरघा में शुरू में दो माह के प्रशिक्षण के बाद पॉकेट मनी के लिए शौकिया तौर पर कार्य शुरू किया। उसके बाद अगस्त 2023 से एक साल की ट्रेनिंग निगम से प्राप्त की। इस दौरान एक खद्दी और हर महीने 2400 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई। अब एक कुशल कारीगर के तौर पर शॉल, मफलर तैयार कर रही हैं और हर महीने आठ से दस हजार कमा रही हैं। इसके अतिरिक्त ग्वाड़ गांव की उमा देवी भी खद्दी कार्य से अच्छी आमदन कमा रही हैं।

हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम जिला मंडी के प्रभारी एवं सहायक प्रबंधक अक्षय सिंह डोट ने बताया कि प्रदेश सरकार हथकरघा व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए निगम के माध्यम से लघु अवधि के विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करती है। जिला में हाल ही में 90 से अधिक लोगों को एक साल का हथकरघा बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान लगभग तीस लाख रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई है।

मछली पालन व्यवसाय बना स्वरोजगार का उत्तम साधन

उपमंडल पधर में किसान अब पारम्परिक खेती के साथ ही मत्स्य पालन कर अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उपमंडल की ग्राम पंचायत कुन्नू के सपेड़ी गांव के दीनानाथ ने मछली पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाकर स्वरोजगार के नए साधन सृजित किए हैं।

दीनानाथ बताते हैं कि वह परिवार का पालन-पोषण करने के लिए खेतीबाड़ी का काम करते हैं। इस कार्य से घर का खर्च चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए कुछ नया करने के बारे में सोचा। इस बीच उन्हें मछली पालन के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने इस व्यवसाय को शुरू करने का मन बना लिया।

दीनानाथ बताते हैं कि उन्हें पता चला कि प्रदेश सरकार भी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ऐसे में उनका हौसला और बढ़ा तथा विभाग से समय-समय पर सहयोग भी मिला। उन्होंने मत्स्य पालन को व्यावसायिक तौर पर शुरू करने के लिए दो टैंकों का निर्माण किया। इनमें से एक टैंक के निर्माण पर लगभग 75 हजार रुपए का खर्च आया। उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से इस पर 50 प्रतिशत अनुदान भी मिला। दूसरे टैंक का निर्माण उन्होंने हाल ही में किया जिस पर लगभग 1.50 लाख रुपए व्यय हुए। कृषि विभाग कार्यालय पधर के माध्यम से उन्होंने इस पर भी 50 प्रतिशत अनुदान के लिए आवेदन किया है।

दीनानाथ बताते हैं कि अभी उन्होंने छोटे यूनिट में मछली पालन का कार्य आरंभ किया है। इस यूनिट

से मछली का अच्छा उत्पादन हुआ और अब इसे आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। उन्होंने अपने टैंक में कॉर्प फिश का बीज डाला था जो कृषि विभाग कार्यालय पधर की ओर से उन्हें निःशुल्क दिया गया। इससे मछली का बेहतर उत्पादन हुआ और चार से छः माह के अंतराल में 300 से 500 ग्राम वजन तक यह पहुंच चुकी हैं। मछलियां घर में ही अच्छे दाम पर 300 रुपए प्रति किलो तक बिक रही हैं। उन्होंने किसान हितैषी योजनाएं चलाने के लिए प्रदेश सरकार विशेषतौर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया है।

विषयवाद् विशेषज्ञ सोनम कुमारी ने बताया कि दीनानाथ को जल से कृषि को बल योजना के तहत 36 हजार रुपए की अनुदान राशि टैंक निर्माण के लिए दी गई है। उन्होंने बताया कि उपमंडल पधर में फिश फार्मिंग के तहत 5 किसानों को टैंक की मुरम्मत के लिए 25 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त कॉर्प फिश का बीज भी दिया गया है। कृषि विभाग की तरफ से उपमंडल पधर के लगभग 1500 किसानों को राष्ट्रीय सतत् कृषि योजना के तहत कृषि से संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।

सुख–आश्रय योजना संवार रही 6000 अनाथ बच्चों का भविष्य

बुनियादी सुविधाओं, समुचित देखभाल और धन के अभाव के साये में पल रहे निराश्रित बच्चों के लिए प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार एक बड़ा सहारा बनी है। यह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की

संवेदनशील और दूरदर्शा सोच का ही नतीजा है कि सरकार ने इन बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ दि स्टेट' का दर्ज़ा प्रदान कर अभिभावक के रूप में इन्हें अपनाया है।

मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बेसहारा बच्चों को अपनाने का संकल्प लिया। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद वह शिमला में टूटीकंडी स्थित बाल आश्रम पहुंचे और वहां रह रहे बच्चों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री सुख–आश्रय योजना बनाने का फैसला किया। इस पहल का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को अन्य बच्चों के समान उचित देखभाल और बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।

हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए कानून के अंतर्गत यह योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 101 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री सुख–आश्रय कोष भी गठित किया गया है। हिमाचल सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए परित्यक्त बच्चों को भी इस योजना के दायरे में शामिल किया है।

राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत इन बच्चों को देश के विभिन्न दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण पर भेजने का प्रावधान किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 'चिल्ड्रन ऑफ दि स्टेट' के पहले दल को 13 दिवसीय भ्रमण पर किया रवाना किया। इस दल में 22 बच्चों को भ्रमण पर भेजा गया है जिनमें 16 लड़कियां और छ: लड़के शामिल हैं। इस दौरान वे चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा का भ्रमण करेंगे।

प्रदेश सरकार ने भ्रमण पर भेजे गए बच्चों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं ताकि वे आनंदपूर्वक अपना समय बिता सकें और मधुर स्मृतियों के साथ वापस लौटें। उनकी आरामदायक यात्रा के लिए शताब्दी ट्रेन और हवाई यात्रा की व्यवस्था की गई है। रात्रि ठहराव के दौरान इनको उन कमरों में ठहराया जा रहा है जिनमें मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी आदि ठहरते हैं।

बच्चों के इस दल ने 2 जनवरी से 4 जनवरी तक का चंडीगढ़ शहर का भ्रमण किया जहां उन्हें हिमाचल भवन में ठहराया गया। 5 जनवरी को वे शताब्दी ट्रेन से दिल्ली पहुंचे और 8 जनवरी तक वहीं ठहरकर विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे। 9 जनवरी को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट हवाई जहाज से गोवा के लिए रवाना होंगे और 13 जनवरी तक गोवा में एक थ्री–स्टार होटल में ठहरेंगे और वहां के विभिन्न पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। 14 जनवरी को ये सभी बच्चे गोवा से हवाई जहाज के माध्यम से चंडीगढ़ पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिह सुक्खू का कहना है कि इन अनाथ बच्चों का हिमाचल की सम्पदा पर बराबर अधिकार है। उनकी सरकार ही माता है और सरकार ही पिता है। जिस प्रकार हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ घूमने जाते हैं, उसी तरह राज्य सरकार ने इन्हें भ्रमण पर भेजा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि भ्रमण करने से ज्ञान बढ़ता है और इसका लाभ बच्चों को आने वाले समय में मिलेगा तथा आने वाले समय में ये बच्चे देश सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

मुख्यमंत्री सुख–आश्रय योजना के अंतर्गत लाभार्थी बच्चों को पढ़ाई के खर्च के अलावा, जेब खर्च के लिए चार हज़ार रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। बाल–बालिका संस्थानों के 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के खाते में हर महीने 1000 रुपये और 15 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग बच्चों एवं एकल महिलाओं के खाते में हर माह 2500 रुपये की धनराशि जमा की जा रही है। निराश्रित बच्चों को स्टार्ट–अप शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इन बच्चों को घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि के प्रावधान के साथ–साथ 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

अनाथ आश्रमों और वृद्धाश्रमों में रहने वालों, निराश्रित महिलाओं और मूक–बधिर बच्चों को सर्दी व गर्मी के कपड़े तथा जूते खरीदने के लिए 10–10 हज़ार रुपये वस्त्र अनुदान के रूप में दिए जा रहे हैं। इसके साथ–साथ विवाह अनुदान के रूप में दो लाख रुपये का प्रावधान भी सरकार ने किया है। मानवीय संवेदनाओं को अधिमान देते हुए अनाथ आश्रम में रहने की उम्र को 26 वर्ष से बढ़ाकर 27 वर्ष किया गया है।

प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख–आश्रय योजना के अंतर्गत 14 अनाथ बच्चों का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलवाया है, जिनकी पढ़ाई का खर्च सरकार वहन कर रही है। कांगड़ा ज़िले के लुथान में लगभग 93 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख–आश्रय परिसर का शिलान्यास किया गया है जहां 400 आश्रितों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

हिमाचल में घरेलू आगजनी आपदा के प्रति रखनी होगी संवेदनशीलता व सक्रिय जागरूकता

–राजन कुमार शर्मा–

जैसा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र है। यहां लगभग हर वर्ष प्रत्येक ऋतु में अलग–अलग तरह की आपदाओं से जान–माल का नुकसान रिकॉर्ड होता आया है।

हिमाचल प्रदेश का लगभग 80% क्षेत्र बर्फबारी व पर्वतीय होने के कारण यहां पर घरों की बनावट व सामग्री में भी अंतर आता है, जिसमें कि अधिक पर्वतीय क्षेत्रों में काठ कुंनी शैली, पेगोड़ा शैली, स्लेट, टिन शेड आदि में घरों का निर्माण किया जाता है। इस शैली में बनाए गए अधिकतर घर अच्छी किस्म के पेड़ों की लकड़ी से तैयार किए जाते हैं, जो कि ज्वलनशील स्वभाव व आग के प्रति भी अति संवेदनशील होते हैं।

इसके अतिरिक्त लंबी सर्दियों व बर्फबारी के मौसम में इन क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं होने की संभावनाएं अन्य ऋतुओं के मुकाबले अत्यधिक बढ़ जाती है। यदि हम पिछले चार–पांच वर्षों की बात करें तो उनके आंकड़ों से पता चलता है कि इस तरह की आपदाएं व घटनाएं दिन प्रतिदिन व प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में यदि हम नववर्ष की बात करें तो 2 जनवरी 2025 को जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल के अंतर्गत टांडी गांव में लगी भीष्ण घरेलू आग से लगभग 17 घर व 6 गौशालाएं जलकर पूरी तरह से राख हो गई। यह भयानक आग लगभग 20 घंटे तक सुलगती रही व इससे लगभग 136 लोग बेघर हुए तथा 10 करोड़ के नुकसान का आंकलन किया गया है। वहीं दूसरी और यदि हम 2 फरवरी 2024 की घटना को याद करें जिसमें की जिला सोलन के नालागढ़ स्थित एक परफ्यूम फैक्ट्री में भयानक आग लग जाने से 1 व्यक्ति की मृत्यु व 30 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। वहीं दूसरी ओर 24 नवंबर 2024 को जिला कुल्लू के तियुन गांव में भयानक आग लग जाने से कई घरों को आग ने अपने आगोश में ले लिया, फलस्वरुप जिससे कि लगभग 80 लाख के नुकसान का आंकलन हुआ था। एक और घटना की यदि हम चर्चा करें तो 3 सितंबर 2023 को जिला शिमला के रोहडू उपमंडल के गांव दरोटी में लगी भीष्ण आग से 9 घर बुरी तरह से जल गए जिसमें की 21 परिवारों के लगभग 74 लोग बेघर व प्रभावित हुए थे। इसके अतिरिक्त एक और घटना 28 अक्तूबर 2021 को जिला कुल्लू के मलाणा गांव में घटित हुई, जिसमें की गांव के कई घरों में एकाएक आग लग जाने से लगभग 16 घर पूरी तरह से जल गए जिसमें की 150 लोग बेघर हो गए थे।

इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त यह कहना उचित होगा कि इस प्रकार की घरेलू आगजनी की घटनाओं में न केवल मनुष्य बल्कि पशुधन भी बुरी तरह से प्रभावित होता है व इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण में भी वृद्धि दर्ज की जाती है। इन भयंकर कड़ाके की सर्दियों में पहाड़ी क्षेत्रों को बर्फ व घने कोहरे व शीतलहर वाले मैदानी क्षेत्रों में भी दम घुटने जैसी घटनाओं में वृद्धि होती है। इसका मुख्य कारण अंगीठी व हिटरों का सोते समय पूरी रात प्रयोग करना पाया गया है। जिससे कि बंद कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर इनके द्वारा उत्सर्जित कार्बन–मोनोऑक्साइड गैस की अत्यधिक वृद्धि होने से मृत्यु व अन्य तरह की बीमारियां लग जाने का खतरा भी शामिल है। अत: संबंधित विभागों द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम व चेतावनी संदेश आमजन के हितों के लिए जारी किए जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए केवल जागरूकता एवं समय–समय पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करके ही हम भविष्य में हिमाचल प्रदेश में होने वाली इस तरह की घरेलू आगजनी इत्यादि घटनाओं पर नियंत्रण पाने में सक्षम व सफल हो पाएंगे।

भारत श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार

शिमला। परिवार कल्याण मंत्रालय के डीजीएचएस की अध्यक्षता में पिछले कुछ सप्ताह में चीन में सांस संबंधी बीमारियों के बढ़ते मामलों की रिपोर्ट के मद्देनजरस्वास्थ्य एवं संयुक्त निगरानी समूह (जेएमजी) की बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), आपदा प्रबंधन (डीएम) सेल, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), आपातकालीन चिकित्सा राहत (ईएमआर) प्रभाग और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञानसंस्थान, दिल्ली सहित अस्पतालों के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

विस्तृत चर्चा के बाद और वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बनी:

चीन में फ्लू के मौसम को देखते हुए स्थिति असामान्य नहीं है। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि मौजूदा बढ़ौतरी का कारण इन्फ्लूएंजा वायरस, आरएसवी और एचएमपीवी है–जो इस मौसम में होने वाले सामान्य रोगजनक हैं।

सरकार सभी उपलब्ध माध्यमों से स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी चीन की स्थिति के बारे में समय पर जानकारी साझा करने का अनुरोध किया गया है।

ये वायरस भारत सहित विश्व भर में पहले से ही मौजूद हैं।

भारत में इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) और इन्फ्लूएंजा के लिए गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी (एसएआरआई) के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली पहले से ही आईसीएमआर और आईडीएसपी नेटवर्क दोनों के माध्यम से मौजूद है और दोनों के आंकड़ों से पता चलता है कि आईएलआई और एसएआरआई मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है।

अस्पतालों के चिकित्सकों ने भी पुष्टि की है कि अपेक्षित मौसमी बदलाव के अलावा पिछले कुछ सप्ताहों में श्वसन संबंधी बीमारियों के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

आईसीएमआर नेटवर्क अन्य श्वसन वायरस जैसे एडेनोवायरस, आरएसवी, एचएमपीवी आदि के लिए भी परीक्षण करता है और ये रोगजनक भी परीक्षण किए गए नमूनों में असामान्य वृद्धि नहीं दिखाते हैं। एहतियाती उपाय के रूप में, आईसीएमआर द्वारा एचएमपीवी के लिए परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी और आईसीएमआर पूरे वर्ष एचएमपीवी पर निगरानी करेगा।

देश भर में हाल ही में आयोजित आपातकालीन अभ्यास के आंकड़ों से पता चला है कि देश श्वसन संबंधी बीमारियों में किसी भी वृद्धि से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

स्वास्थ्य प्रणालियाँ और निगरानी नेटवर्क सतर्क बने हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश किसी भी स्वास्थ्य चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कोटखाई में सब-जज कोर्ट खोलने की घोषणा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के कोटखाई सीएचसी का दर्जा बढ़ाकर नागरिक अस्पताल करने की घोषणा की है। उन्होंने कोटखाई में उप न्यायाधीश न्यायालय, उप-मंडलीय पशु चिकित्सा अस्पताल, अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान प्रगतिनगर में सिविल व मेकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने के साथ-साथ आईटीआई प्रगतिनगर में डिप्लोमा इन कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग तथा सोलर टेक्नीशियन के नए ट्रेड शुरू

करने की घोषणा की। उन्होंने खलटू नाले तथा चमशु नाले पर पुल निर्माण के लिए पांच-पांच करोड़ रुपए तथा टिक्कर बस स्टैंड के लिए तीन करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपए की लागत से छैला-ओच्छघाट-कुमारहट्टी सड़क को डबल लेन किया जाएगा। उन्होंने इस सड़क की डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जिला शिमला के कोटखाई में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आई आपदा के दौरान राज्य सरकार ने किसी भी बागवान के सेब व अन्य उत्पाद सड़ने नहीं दिये और समय पर मंडी तक पहुंचाया। राज्य सरकार ने आपदा के दौरान जुब्बल-कोटखाई की सड़कों को खोलने के लिए 28 करोड़ रुपए प्रदान किए। उन्होंने कहा, ''मैंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से कहा कि बागवानों की हर संभव सहायता कीजिए और धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। एक भी बागवान अपनी फसल खेत में सड़ने की शिकायत लेकर नहीं आया।''

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 60 करोड़ रुपए नाबार्ड तथा राज्य सरकार के फंड से 16 करोड़ रुपए सड़कों पर खर्च किए हैं। दो वर्ष में कुल 286 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और आने वाले समय में विकास के लिए और धन व्यय किया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मण्डी मध्यस्थता योजना की 163 करोड़ रुपए की देनदारियां क्लीयर की। छोटे सेब बागवानों की मदद करने के लिए हमने इस वर्ष यूनिवर्सल कार्टन लागू किया। अगले वर्ष से यूनिवर्सल कार्टन पर वजन भी लिखा जाएगा। पराला मंडी का निर्माण कार्य पूरा किया और 100 करोड़ की लागत से फल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया। उन्होंने कहा कि सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक डेढ़ रुपए बढ़ाकर 12 रुपए प्रति किलो किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में बागवानी क्षेत्र में और सुधार करेगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि 45 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में छः-छः स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात किए गए हैं और बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने के लिए प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं, ताकि लोगों को राज्य के भीतर ही बेहतर सेवाएं मिल सकें।

डॉ. शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए सोलन जिला के कंडाघाट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रही है। अनाथ बच्चों के लिए राज्य सरकार जिला कांगड़ा के लुथान में मुख्यमंत्री सुखाश्रय परिसर का निर्माण कर रही है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दो करोड़ रुपए मिनी सचिवालय के लिए उपलब्ध करवाए हैं, जिसके बाद इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ने दिन-रात निरंतर कार्य किया । उन्होंने कहा कि भाजपा ने धनबल के सहारे चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया लेकिन जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री इस अग्निपरीक्षा में पास हुए और कांग्रेस के विधायकों की संख्या एक बार फिर 40 हो गई। उन्होंने कहा कि भाजपा का जुब्बल-कोटखाई के साथ लगाव केवल चुनावों के समय ही दिखता है।

रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार मुख्यमंत्री का एजेंडा है तथा अन्य विभागों में भी अनेक सुधार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पर्याप्त धन, सड़कों में सुधार, पेयजल और बिजली आपूर्ति में सुधार के साथ-साथ नए संस्थान भी खोले गए हैं, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार आया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान, ओएसडी रितेश कपरेट व सौरभ चौहान, उपायुक्त अनुपम कश्यप, प्रबन्ध निदेशक एचपीएमसी सुदेश कुमार मोख्टा, विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

22 नई जल विद्युत परियोजनाओं के आबंटन के लिए प्रस्ताव आमन्त्रित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार 22 नई जल विद्युत परियोजनाओं का आबंटन करने जा रही है, जिनकी कुल विद्युत क्षमता 828 मेगावाट है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में 6.5 मेगावाट से लेकर 400 मेगावाट तक की परियोजनाएं शामिल है। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं प्रदेश के कुल्लू, चम्बा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और शिमला जिलों में चिन्हित की गई हैं, जिनमें सबसे अधिक 595 मेगावाट क्षमता की नौ परियोजनाएं चिनाव नदी बेसिन, 169 मेगावाट क्षमता की आठ परियोजनाएं सतलुज नदी बेसिन, 55 मेगावाट की क्षमता की चार परियोजनाएं रावी व एक परियोजना नौ मेगावाट क्षमता की ब्यास बेसिन में लगाना प्रस्तावित है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली बार इन परियोजनाओं को देश के अन्य राज्यों एवं केन्द्र शसित प्रदेशों व अन्य राज्य व केन्द्रीय उपक्रमों को 10 लाख प्रति मेगावाट अपफ्रंट प्रीमियम के आधार पर 40 वर्ष के लिए आबंटित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ऊर्जा निदेशालय द्वारा सभी राज्य के सचिवों व केन्द्रीय उपक्रमों को पत्र भी भेजा गया है। उन्होंने कहा इन परियोजनाओ के आबंटन के लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन भी जारी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के लगने से बिजली की आपूर्ति, मुफ्त बिजली के रूप में राजस्व में बढ़ोतरी, स्थानीय लोगों को रोजगार व स्थानीय क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित होगा। हिमाचल प्रदेश देश के एक समृद्धतम राज्य के रूप में उभरेगा।

काजा में दो मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र काजा में बिजली व्यवस्था को सुनिश्चित और सुचारू बनाने के लिए दो मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है जिसके लिए बिजली बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने युद्धस्तर पर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में एक एम.डब्ल्यू.एच. बैटरी स्टोरेज को भी इसमें जोड़कर प्लांट को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को 'ग्रीन स्टेट' बनाने के लिए सोलर पावर का अधिक से अधिक दोहन करने का प्रयास कर रही है तथा मांग के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों में ई.वी. चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली बोर्ड के कार्यालयों के आस-पास की खाली जमीन पर 18 मेगावाट की ग्राऊंड मांउटिड तथा रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वर्ष 2026-27 तक प्रदेश में 50,000 उपभोक्ताओं के घरों पर रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए अभी तक 4444 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्चों को नियंत्रित किया जा रहा है, जिसके तहत विद्युत सब्सिडी और स्टाफ का युक्तिकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से बिजली बोर्ड द्वारा किए गए विद्युत परियोजना समझौतों की समीक्षा की जा रही है तथा बोर्ड द्वारा उच्च दरों पर लिए गए ऋणों की भी समीक्षा की जाएगी ताकि कम ब्याज दरों पर ऋण भुगतान किया जा सके और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को ऋण के बोझ से निकालकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है तथा सरकार द्वारा उन्हें समय-समय पर वित्तीय लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं।

अप्रैल, 2025 से बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता

करते हुए कहा कि प्रदेश में अप्रैल, 2025 में बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीपीएल सूची में केवल पात्र परिवारों को ही सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जाये तथा इस संबंध में नए मापदंड तैयार किए जायें। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि इन मापदंडों को 5 जनवरी, 2025 से पहले तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा इसके उपरान्त, इस संबंध में मंत्रिमंडल से स्वीकृति ली जाएगी। नए दिशा-निर्देशों को जनवरी, 2025 में होने वाली ग्रामसभा में आम जनता के साथ साझा किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ग्रामसभा द्वारा अनुशंसित बीपीएल परिवारों की सूचियों का सत्यापन करने के लिए उप-मंडल स्तर पर उप-मंडलाधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी की दो सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए ताकि पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। उन्होंने पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने पर बल दिया ताकि इन परिवारों को लाभ से वंचित न होना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बीपीएल परिवारों के चयन के लिए वार्षिक आय में संशोधन पर विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल परिवारों की अंतिम सूची से संबंधित कोई भी आपत्ति संबंधित उपायुक्त और मंडलायुक्त को प्रस्तुत की जा सकती है, उनके पास इन शिकायतों की समीक्षा और समाधान करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के विभिन्न उत्पादों के प्रदर्शन और होम डिलीवरी के लिए एक वेबसाइट भी शुरू की जाएगी।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजेश शर्मा, निदेशक राघव शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

झूठ बोलने की बजाये दिल्ली में हिमाचल के हित उठाएं जय राम ठाकुर:अवस्थी

शिमला/शैल। विधायक संजय अवस्थी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने मात्र दो वर्ष में ही 31 हजार सरकारी नौकरियां निकाली हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर हर दिन नया झूठ बोलते हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि जय राम ठाकुर को अपने कार्यकाल के पांच वर्षों का हिसाब भी प्रदेश की जनता को देना चाहिए। वास्तविकता यह है कि पूर्व भाजपा सरकार के समय पूरे पांच वर्षों में 20 हजार नौकरियां प्रदान की तथा वर्तमान कांग्रेस सरकार ने मात्र दो वर्षों में 31 हजार नौकरियां निकाली हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नौकरियां कानूनी पेचीदगियों में फंसी रही और प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा किया गया। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार का गठन हुआ तो हमने प्राथमिकता के आधार पर अदालतों में मजबूती से पैरवी कर परिणाम निकलवाए और युवाओं के लिए सरकारी रोजगार का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा राज्य सरकार स्वरोजगार को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना भी शुरू की है, जिससे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

संजय अवस्थी ने कहा कि अगर भाजपा नेता हिमाचल प्रदेश के इतने ही बड़े हिमायती हैं तो वह दिल्ली जाकर केन्द्र सरकार के पास राज्य के हितों को प्रमुखता से उठाएं, ताकि प्रदेश के लोगों को उनका हक मिल सकें। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता केंद्र से मिलने वाले हक को भी रुकवाने में लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आये डेढ़ वर्ष से अधिक समय हो गया है लेकिन आपदा प्रभावितों के लगभग 10 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। इसके अलावा एनपीएस के लगभग नौ हजार करोड़ रुपये पर भी केंद्र सरकार कुंडली मारकर बैठी है। ऐसे में भाजपा नेताओं को इन बातों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाकर हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित में कार्य करना चाहिए।

स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट का शुभारंभ किया:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकसित ई-कॉमर्स वेबसाइट himira.co.in का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से प्रदेश के 44 हजार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3,50,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम-ईरा महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है और आने वाले समय में इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने सभी स्वयं सहायता समूहों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने को कहा ताकि उन्हें अधिक से अधिक

द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस वेबसाइट से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को वैश्विक मंच उपलब्ध होगा, जिससे ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को विस्तार मिलेगा और ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आय सृजन के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सात फूड वैन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया।

लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्रियों और अन्य गणमान्यों को भी हिम-ईरा से बने उत्पाद उपहार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हिम-ईरा के उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनकी बिक्री के लिए प्रदेश सरकार, सरकारी भवनों में इन उत्पादों के लिए एक समर्पित दुकान उपलब्ध करवाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य की संस्कृति के अनुरूप नीतियां निर्धारित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और वनों में पौध रोपण जैसे कार्यों में महिलाओं और युवा समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है जिसके तहत उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुधार की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश के संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर हिमाचल वर्ष 2032 तक देश का समृद्धशाली राज्य बनेगा।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब व वंचित वर्गो को ध्यान में रखते हुए नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चत कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में अनेक सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। हिम-ईरा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए आय के नए स्रोत सृजित करने में सहायक सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम में लिफ्ट के निकट राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भूमि आबंटित गई की है जहां प्रदेश के हर जिला से संबंधित एक दुकान स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पाद प्रदर्शित करने और बिक्री करने के लिए नियमित रूप से प्रदर्शनियों और मेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध करवाई गई फूड वैन का संचालन और प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में स्वयं सहायता समूहों को 70 फूड वैन उपलब्ध करवाने की योजना है।

मुख्यमंत्री 'हर दिन सेहत' अभियान का किया शुभारंभ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ओकओवर शिमला से 'हर दिन सेहत' अभियान

का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह व्यापक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, हिमाचल प्रदेश के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और बीमारियों की रोकथाम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत आईजीएमसी शिमला और सिस्टर निवेदिता नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी विभिन्न स्थानों पर हेल्थ टॉक्स का आयोजन करेंगे और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में जागरूक करेंगे। ये गतिविधियां आईजीएमसी शिमला के विभिन्न वार्डो, ओपीडी और शिमला नगर निगम के अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य बीमारियों की रोकथाम, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं एवं योजनाओं के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान एक दीर्घकालिक पहल के रूप में कल्पित किया गया है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना और हिमाचल प्रदेश को एक स्वस्थ, अधिक जागरूक समाज में परिवर्तित करना है। यह पहल राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य को सतत् और समावेशी दृष्टिकोण से सुधारने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय डॉ. राहुल राव तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

हिमाचल के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों ने विश्व भर में बनाई पहचानः जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी नेनई दिल्ली के दिल्ली हाट में, हिम महोत्सव का शुभारंभ किया जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश

चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और यहां के उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बने उत्पाद वैश्विक तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।

सरकार द्वारा एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से किया गया है।

यह महोत्सव 1 से 15 जनवरी, 2025 तक नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आयोजित किया जा रहा है, जहां कारीगरों द्वारा हिमाचली हस्तशिल्प और बुनकर उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 60 स्टॉल लगाए गए हैं।

हिमाचली धाम और हिमाचली सांस्कृतिक कार्यक्रम महोत्सव का विशेष आकर्षण होंगे।

पर्यटन विभाग, भाषा कला एवं संस्कृति विभाग और हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड संयुक्त तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।

इस मौके पर राजस्व मंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का अन्य राज्यों और शहरों में भी आयोजन किया जाना

उन्होंने कहा कि यह आयोजन एनसीआर के लोगों को हिमाचल प्रदेश के उत्कृष्ट हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का लोक संगीत और लोक नृत्य दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, जिससे स्थानीय कलाकारों को व्यापक मंच उपलब्ध हो रहा है।

राजस्व मंत्री ने स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने लोगों से हिमाचल प्रदेश का भ्रमण करने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य देश में सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बर्फ से लकदक पहाड़, हरे-भरे घास के मैदान, ठंडे रेगिस्तान के अलावा झीलें और जल क्रीड़ाएं भी हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आर.डी. नजीम ने अपने स्वागत भाषण में स्थानीय हस्तशिल्प के साथ-साथ बुनकरों और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की पहलों के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में हिम महोत्सव का दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है। बीते वर्ष इसे बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली थी और लोगों ने उत्पादों की सराहना की थी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के शिल्प, व्यंजनों और समृद्ध संस्कृति का जश्न मनाना है।

राजस्व मंत्री ने कारीगरों को उनके विशिष्ट कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्कृष्टता अवॉर्ड भी प्रदान किए। पारंपरिक शिल्प संरक्षण श्रेणी में ओपी मल्होत्रा, रितु धीमान और पूनम एंड बलवीर (काष्ठशिल्प) को पुरस्कार प्रदान किया गया। नवाचार हस्तशिल्प श्रेणी में इंदिरा देवी (कुल्लवी व्हिम्स) और ईशा (पारंपरिक ज्वेलरी) को पुरस्कार प्रदान किया गया। युवा कारीगर श्रेणी का पुरस्कार वीर सिंह (धातु शिल्प), अजय शर्मा (हस्तशिल्प) और जगदीश (हस्तशिल्प) को प्रदान किया गया। कम्यूनिटी इंपैक्ट पुरस्कार अंशुल मल्होत्रा और राजन मिन्हास को प्रदान किया गया। हिमाचल के कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

पर्यटन अधोसंरचना निर्माण व सुदृढ़ीकरण पर खर्च होंगे 2415 करोड़ रुपयेः मुख्यमंत्री

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सुक्खू ने पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि पर्यटन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य स्तम्भ है। राज्य सरकार

विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने को प्राथमिकता दे रही है ताकि पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण पर आने वाले समय में 2415 करोड़ रुपये व्यय करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मंडी में बनने वाले शिवधाम पर 150.27 करोड़ रुपये तथा जिला हमीरपुर के बाबा बालक नाथ मन्दिर के सौन्दर्यीकरण पर 51.70 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसी प्रकार 78.09 करोड़ रुपये की लागत से जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां तथा पालमपुर नगर का सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। प्रदेश सरकार 280.39 करोड़ की लागत से जिला हमीरपुर के नादौन, जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां और जिला कुल्लू के मनाली व कुल्लू में वैलनैस सेन्टर विकसित करेगी। जिला कुल्लू के नग्गर किले के संरक्षण व मरम्मत कार्य पर 8.64 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है और इस कड़ी में नादौन में राफ्टिंग कॉम्पलैक्स और मनाली, धर्मशाला तथा शिमला में रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण किया जाएगा। इन पर 163.50 करोड़ रुपये व्यय होंगे जिससे पर्यटकों सहित स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेहतर हवाई सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार हेलीपोर्ट का निर्माण कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को इन परियोजनाओं के कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को डीजीसीए जिला शिमला के संजौली, रामपुर, जिला मंडी के कंगनीधार और जिला सोलन के बद्दी हेलीपोर्ट सहित मौजूदा अन्य हेलीपोर्ट के लिए परिचालन स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश भी दिए, ताकि इन हेलीपोर्ट में हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन सुगम हो सके।

सुक्खू ने कहा कि पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं और सरकार इन क्षेत्रों के विकास और अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पर्यटकों की आमद बढ़ी है, जो प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण साबित हो रही है।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने पर्यटन क्षेत्र में सुधार के लिए अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015
www.shailsamachar.com

300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की जगह बिजली सब्सिडी बन्द करने पर पहुंची सरकार

- आरबीआई के मुताबिक प्रदेश का कर्ज़ भार जीडीपी के 42.5% तक पहुंचा
- पंजाब के बाद कर्ज भार में दूसरे स्थान पर पहुंचा हिमाचल
- सरकार के फैसलों से हाईकमान भी आई कठघरे में

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार द्वारा बिजली पर दी जा रही सब्सिडी छोड़ दी है। सब्सिडी छोड़ने की घोषणा उन्होंने वाकायदा एक पत्रकार वार्ता बुलाकर उसमें की है। उन्होंने कहा है कि उनके नाम पर पांच बिजली के मीटर हैं और उन पांचों मीटरों पर मिल रही सब्सिडी उन्होंने छोड़ दी है। पत्रकार वार्ता में ही सब्सिडी छोड़ने का फॉर्म भरकर बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को सौंप दिया। उन्होंने दूसरे संपन्न

लोगों से भी यह सब्सिडी छोड़ने का आग्रह किया। उनके आग्रह पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने भी तुरन्त यह सब्सिडी छोड़ने का फॉर्म भर दिया। मुख्यमंत्री और विक्रमादित्य सिंह दोनों ही निश्चित रूप से संपन्न व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए उन्हें यह सब्सिडी छोड़नी ही चाहिए थी। उन्हीं की तरह दूसरे संपन्न राजनेताओं को भी ऐसा ही अनुसरण करना चाहिए। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए इस आशय का शायद आदेश भी जारी कर दिया है। जो शायद सेवानिवृत्त लोगों पर भी बराबर लागू होगा। सरकार के इस आदेश से स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश वित्तीय संकट से गुजर रहा है। वित्तीय संसाधन जुटाना के लिये जिस तरह के फैसले इस सरकार ने लिये हैं जिन सेवाओं और वस्तुओं पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर भार बढ़ाया है उससे जो सवाल खड़े हुये उसे न केवल प्रदेश कांग्रेस बल्कि कांग्रेस हाईकमान तक सवालों के घेरे में आ जाता है।

सुक्खू सरकार को सत्ता में आये दो वर्ष हो गये हैं। मंत्रिमण्डल का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो पहली बार ही विधायक बना हो। हर सरकार हर वर्ष बजट विधानसभा में रखती है और पास करवाती आयी है। हर बजट कर मुक्त बजट प्रचारित होता रहा है। हर बजट में प्रदेश की वित्तीय स्थिति का पूरा विवरण माननीय के सामने आता है। हर वर्ष कैग रिपोर्ट और आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा के पटल पर रखे जाते रहे हैं और आगे भी रहेंगे ही। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि किसी भी राजनीतिक दल को चुनावों में उतरते वक्त अपना घोषणा पत्र जारी करते हुये प्रदेश की वित्तीय स्थिति की जानकारी न रही हो। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक हो जाता है कि जब दो वर्ष पहले कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की जनता को दस गारंटीयां दी थी तब उसे प्रदेश की वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी रही ही होगी। लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरह का आचरण गारंटीयों को लेकर सरकार का रहा है और जिस तरह से शौचालय शुल्क लगाने तक स्थिति आ पहुंची है उससे कुछ अलग ही तस्वीर उभरती है। क्योंकि हर जिस तरह के 'किन्तु -परन्तु' की शर्तें लगाई गयी हैं उससे हर गारंटी की लाभार्थियों के आंकड़ों में जो व्यवहारिक कमी आयी है उसने सरकार की नीयत और नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं। सरकार के फैसले राष्ट्रीय स्तर पर निन्दा और चर्चा का विषय बने हैं। प्रधानमंत्री तक ने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में हिमाचल के फैसलों पर कांग्रेस की समझ पर कड़े हमले किये हैं। बल्कि हिमाचल के फैसले ही प्रधानमंत्री की आक्रमकता का आधार बने हैं।

जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लगने शुरू हुये हैं उससे कांग्रेस की कार्यशैली और खर्चों पर न चाहे ही सरकार के गठन से लेकर अब तक नजर जानी शुरू हो गयी है। जिस सरकार को हर माह कर्ज लेना पड़ रहा हो वहां मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रस्तावित कायाकल्प पर 19 करोड़ के खर्च का अनुमान स्वभाविक रूप से विपक्ष के निशाने पर आयेगा ही। क्योंकि रिजर्व बैंक की 2024 में आयी रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज भार में हिमाचल राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। पंजाब का कर्ज जीडीपी के अनुपात में 44.1% है और हिमाचल 42.5% है। जहां कर्ज जीडीपी का 42.5 प्रतिशत पहुंच जाये वहां पर विकास सिर्फ राजनेताओं के भाषणों तक ही सीमित रहता है जमीन पर नहीं पहुंचता है। क्योंकि सारे संसाधन इस कर्ज का ब्याज चुकाने में ही लग जाते हैं और जब सरकार अपने खर्चों पर लगाम लगाने में सक्षम न रह जाये तो स्थिति और भी भयानक हो जाती है। जो पार्टी दो वर्ष पहले 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वायदा करके आयी हो उसे आज सब्सिडी छोड़ने के आदेश और आग्रह करने पड़ जायें उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। बल्कि सरकार के फैसले हाईकमान के लिये विश्वसनीयता का संकट खड़ा करते जा रहे हैं।

टैंकर सप्लाई घोटाले से

.....पृष्ठ 1 का शेष

राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहना अनिवार्य हो जाता है। फिर इसमें पैसा एस डी आर एफ और एन डी आर एफ से दिया गया है। विपक्ष बहुत अरसे से आपदा राहत में घोटाला होने का आरोप लगाता आया है जो इससे स्वत: ही प्रमाणित हो जाता है। केंद्र पर भी इस घोटाले का प्रभाव पड़ेगा। केंद्र आसानी से राज्य के किसी भी आग्रह को भविष्य में स्वीकार नहीं कर पायेगा। कांग्रेस हाईकमान भी इस घोटाले को सामने रखते हुये प्रदेश नेतृत्व को लम्बे अरसे तक अभयदान नहीं दे सकेगी। और न ही इस घोटाले को विपक्ष की सरकार गिराने की चाल करार दे पायेगी। बल्कि यह घोटाला कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल उठाने का कारण बन जायेगा।

रेरा में अध्यक्ष और सदस्यों

.....पृष्ठ 1 का शेष

इन निर्देशों के परिदृश्य में यह सवाल उठने लगा है कि क्या सुक्खू सरकार केन्द्र के निर्देशों की अवहेलनायक कर पायेगी? क्या अधिकारी इन निर्देशों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लायेंगे? यह सवाल इसलिये उठ रहे हैं क्योंकि इन पदों के लिये आवेदन आमंत्रित करने के लिये जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें विजिलैन्स क्लीयरैन्स हासिल करने का कोई संकेत तक नहीं दिया गया है।

यह है आवेदन आमंत्रित करने के लिये जारी हुआ विज्ञापन।

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
HOUSING DEPARTMENT
ADVERTISEMENT

One post of Chairperson and two posts of Members, HP RERA is to be filled up as per RERA Act/ HP RERA Rules.

Now, therefore, applications are invited under the provision of the Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016 from the eligible candidates for appointment as Chairperson and two whole time Members of Real Estate Regulatory Authority in the State of Himachal Pradesh.

The candidates should have adequate knowledge of and professional experience of at least 20 years in case of the Chairperson and 15 years in the case of the Members in the field of Urban Development, Housing, Real Estate Development, Infrastructure, Economics, Technical Experts from relevant fields, planning, Law, Commerce, acccountancy, industry, Management, social Service, Public Affairs or Administration.

Provided that a person who is, or has been, in the service of the State Government shall not be appointed as a Chairperson unless such person has held the post of Additional Secretary to the Central Government or any equivalent post in the Central or State Government.

Provided further that a person who is, or has been, in the service of the State Government shall not be appointed as a Member unless such person has held the post of Secretary to the State Government or any equivalent post in the State Government or Central Government.

Other terms & conditions shall be as per the Himachal Pradesh Real Estate (Regulation & Development) Rules, 2017 available on website https://hprera.nic.in/.

Candidates are requested to submit their complete biodata/ profile and qualification for the post applied for.

The eligible candidates may submit their applications through registered post or in person latest by 23rd January, 2025 (upto 5.00 PM) on the following address:-

Under Secretary (Housing) to the
Government of Himachal Pradesh.
Room No. 518, Armsdale Building,
HP Secretariat, Shimla-2
Phone No. 01772628504

Secretary (Housing) to the
Government of Himachal Pradesh